



**भारतीय मानक ब्यूरो**

**गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए झांकी परिकल्पित, निर्मित और प्रदर्शित करने के लिए एजेंसी  
को अनुबंधित करने हेतु रुचि अभिव्यक्ति (EoI)**

भारतीय मानक ब्यूरो  
मानक भवन  
9, बहादुर शाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली - 110002

संदर्भ : पीआरडी/टैब्लू (2021-22)

## विषय सूची

पैरा संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
-	दावा त्याग	4
	प्रस्ताव हेतु निवेदन सूचना	5
	महत्वपूर्ण डाटा शीट	6
	अनुसूची – I बोलीदाताओं के लिए जानकारी	7
1.1	-	
1.2	परिभाषाएं	7
1.3	ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया	8
1.4	बोली तैयार और जमा करने की लागत	10
1.5	बोली की भाषा	10
1.6	बोली पूर बैठक	11
1.7	पूर्व अर्हता लिफाफा	11
1.8	संविदा की अवधि	12
1.9	संशोधन	12
1.10	हित टकराव	12
1.11	सशर्त बोली	13
1.12	उप संविदा	13
	अनुसूची – II-विचारार्थ विषय	14
2.1	रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देश	14
2.2	ब्यूरो के क्रियाकलापों का संकलप्ना नोट	14
2.3	ब्यूरो की झांकी की विषय-वस्तु	14
2.4	बोलीदाता के कार्य	14
2.5	कार्यों को पूरा करने का कार्यक्रम.	14
2.6	ब्यूरो द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता या इनपुट	15
	अनुसूची III-पात्रता और पूर्वअर्हता मानदंड	15
3.1	पूर्वअर्हता मानदंड	15
3.2	तकनीकी मूल्यांकन का मानदंड	16

	अनुसूची IV बोलियों का मूल्यांकन	17
4.1.1	बोलियों की प्राथमिक जांच – अनुक्रियता निर्धारण	17
4.1.2	क्षीणता या अनियमतिता या अनुपालनहीनता – मूलभूत या मामूली	17
4.1.3	बोलियों का स्पष्टीकरण और त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़	18
4.1.4	मूल्यांकन के दौरान ब्यूरो से संपर्क	18
4.2	किसी बोली को स्वीकार और किसी या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार	18
	अनुसूची VI	19
	संलग्नक I बोली पूर्व सूचना प्रारूप	20
	संलग्नक II रक्षा मंत्रालय की आवश्यकता अनुरूप बहुविध झांकियों से संबंधित शपथपत्र	21
	संलग्नक III वित्तीय बोली प्रारूप	22
	संलग्नक IV संकल्पना नोट और ब्यूरो का परिचय तथा इसकी महत्त्वपूर्ण गतिविधियां	29
	संलग्नक V सामान्य वित्तीय नियम 201 के नियम 144 (XI) के प्रावधानों का सार	34
	संलग्नक - VI बोलीदाता के लैटरहेड पर कालीसूची, अभियोग या आपराधिक अपराध या सजा संबंधी घोषणा	35
	अनुसूची VII बोलीदाता के लैटरहेड पर पूर्व संविदा की समाप्ति	36

	और हित टकराव संबंधी घोषणा	
	अनुसूची VIII सार्वजनिक प्राप्ति में निष्ठा संहिता द्वारा अनुपालन की घोषणा	37
	अनुसूची IX निष्ठा अनुबंध	38

## दावा त्याग

1. इस रूचि अभिव्यक्ति (Eol) में निहित जानकारी भारत के गणतंत्र दिवस 2022 के दौरान झांकी की परिकल्पना, निर्माण और प्रदर्शन हेतु एजेंसी को अनुबंधित करने के लिए है।
2. रूचि अभिव्यक्ति दस्तावेज़ सेवाओं के लिए अनुशंसा, अनुबंध में प्रविष्ट करने का प्रस्ताव या आमंत्रण, करार या अन्य कोई करार नहीं है। सेवाओं का प्रावधान ब्यूरो और किसी ठेकेदार के बीच सहमत ब्यूरो द्वारा यथा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुपालन और उपयुक्त प्रलेखन के अधीन, दस्तावेज़ में दी गई चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत है।
3. निविदा प्रक्रिया से तब तक किसी प्रकार की कोई संविदागत बाध्यता नहीं होगी जब तक कि ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी और सफल बोलीदाता (बोलीदाता जिसकी बोली ब्यूरो द्वारा स्वीकार की गई हो) के बीच औपचारिक करार निष्पादित नहीं हो जाता।
4. इस रूचि अभिव्यक्ति का प्रयोजन बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके प्रस्ताव को तैयार करने में सहायता हेतु जानकारी प्रदान करना है। यह रूचि अभिव्यक्ति प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक सभी जानकारी निहित होने का दावा नहीं करती है। प्रत्येक बोलीदाता इस रूचि अभिव्यक्ति में निहित जानकारी की संपूर्णता के लिए स्वयं अध्ययन या जांच और विश्लेषण करें और यथा आवश्यकता स्वतंत्र सलाह लें। ब्यूरो इस रूचि अभिव्यक्ति में दी गई ऐसी जानकारी की संपूर्णता से संबंधित किसी प्रकार के दायित्व का वहन नहीं करता है जो बोलीदाता को बोली देने के लिए आवश्यक हो सकती है। ब्यूरो अपने सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर प्राप्त किसी या सभी बोलियों को निरस्त करने के अतिरिक्त रूचि अभिव्यक्ति की किसी शर्त को शुद्धिपत्र के प्रकाशन द्वारा संशोधित करने का अधिकार रखता है।
5. ब्यूरो अपनी पूर्ण विवेकाधिकार से परंतु ऐसा करने की बाध्यता के बिना इस रूचि अभिव्यक्ति को अद्यतन, संशोधित या अनुपूरक कर सकता है। इस रूचि अभिव्यक्ति में इस प्रकार के किसी परिवर्तन या संशोधन, यदि हो, को ब्यूरो की वेबसाइट और सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सीपीपी) पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
6. प्रस्तावों की प्राप्ति में किसी प्रकार के विलंब के लिए ब्यूरो उत्तरदायी नहीं होगा। इस रूचि अभिव्यक्ति को जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि ब्यूरो सेवाओं के लिए बोलीदाता का चयन करने या चयनित बोलीदाता को नियुक्त करने, जैसा भी मामला हो, के लिए बाध्य है और ब्यूरो किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए रूचि अभिव्यक्ति दस्तावेज़ के लिए प्राप्त किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने का

अधिकार रखता है। ब्यूरो सभी बोली देने वालों को सूचित करते हुए किसी भी चरण में प्रक्रिया को रोकने या वापिस लेने का अधिकार भी रखता है।

## रुचि अभिव्यक्ति हेतु निवेदन के लिए सूचना

1. भारतीय मानक ब्यूरो (द ब्यूरो), भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
2. इस रुचि अभिव्यक्ति दस्तावेज़ में वर्णित सेवाएं प्रदान करने हेतु, ब्यूरो सीपीपी पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app portal>) के माध्यम से बोली देने की नियत समाप्ति तिथि पर या उससे पूर्व योग्य और अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं से रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।
3. रुचि अभिव्यक्ति दस्तावेज़ में वर्णित रुचि अभिव्यक्ति प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निविदाकारों को ही प्रस्ताव निवेदन (आरएफपी) दस्तावेज़ जारी किया जाएगा। यह आरपीएफ दस्तावेज़ में वर्णित सेवाओं के प्रदान हेतु सीपीपी पोर्टल के माध्यम से निविदा में शामिल होने के लिए निविदा प्रस्तुतीकरण से पहले चयनित निविदाकारों के तकनीकी और आर्थिक निविदा वाले द्विनिविदा प्रणाली पर आधारित होगा।
4. भारतीय मानक ब्यूरो मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से देश की सेवा करने और अपने स्थापना के 75 साल पूरे करने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर को मनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ब्यूरो 2022 की गणतन्त्र दिवस परेड में अपनी झांकी निकालने का प्रस्ताव बनाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्यूरो एक ऐसी अनुभवी एजेंसी को अनुबंधित करना चाहता है जो भारत की 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झांकी की परिकल्पना, निर्माण और प्रदर्शन करने में सक्षम हो। इसके लिए प्रतिष्ठित, योग्य और अर्हता प्राप्त एजेंसियों से रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। एजेंसी ब्यूरो की स्थापना से लेकर अब तक की उसकी यात्रा में ब्यूरो के प्रमुख कार्यों द्वारा हासिल उपलब्धियों को झांकी के माध्यम से दर्शाने में सक्षम हो। रुचि अभिव्यक्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

1)	पात्रता मानदंड	रुचि अभिव्यक्ति के पैरा 3.1 के अनुसार
2)	संविदा की वैधता	गणतंत्र दिवस परेड 2022 दौरान झांकी के निर्माण और प्रदर्शन तक और संबद्ध कार्य
3)	रुचि अभिव्यक्ति दस्तावेज़ की उपलब्धता	(क) सीपीपी पोर्टल <a href="http://www.eprocure.gov.in">www.eprocure.gov.in</a> (ख) ब्यूरो की वेबसाइट <a href="http://www.bis.gov.in">www.bis.gov.in</a> (केवल संदर्भ हेतु)
4)	जमा करने का	सीपीपी पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन

	तरीका	
5)	बोली प्रणाली और लिफाफा	आरएफपी चरण में द्विबोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय बोली दो अलग लिफाफो में)
6)	बोलियों की वैधता	बोली जमा करने की तिथि से 90 दिन
7)	रूचि अभिव्यक्ति की लागत	शून्य

5. ब्यूरो बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या निरस्त करने तथा ब्यूरो के हित को सर्वोत्तम रूप से पूरा करने वाले बोलीदाता (बोलीदाताओं) को चयन करने का अधिकार रखता है।





**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**Expression of Interest (EoI) for Engagement of Agency  
for Conceptualizing, Fabricating and Displaying a Tableau for Republic Day Parade 2022**

**Bureau of Indian Standards  
Manak Bhawan  
9, Bahadur Shah Zafar Marg  
New Delhi- 110002**

**Reference: PRD/Tableau (2021-22)**

## **TABLE OF CONTENTS**

PARA NUMBER	CONTENT	PAGE NUMBER
-	DISCLAIMER	4
	NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL	5
	CRITICAL DATE SHEET	6
	SCHEDULE – I INFORMATION TO BIDDERS	7
1.1	-	
1.2	DEFINITIONS	7
1.3	PROCEDURE OF ONLINE BID SUBMISSION	8
1.4	COST OF BID PREPARATION AND SUBMISSION	10
1.5	LANGUAGE OF BID	10
1.6	PRE-BID MEETING	11
1.7	PRE-QUALIFICATION ENVELOPE	11
1.8	PERIOD OF CONTRACT	12
1.9	AMENDMENT	12
1.10	CONFLICT OF INTEREST	12
1.11	CONDITIONAL BIDS	13
1.12	SUBCONTRACTING	13
	SCHEDULE – II-TERMS OF REFERENCE	14
2.1	GUIDELINES OF MINISTRY OF DEFENCE	14
2.2	CONCEPT NOTE OF THE ACTIVITIES OF THE BUREAU	14
2.3	THE THEME FOR THE BUREAU'S TABLEAU	14
2.4	TASKS TO BE CARRIED OUT BY THE BIDDER.	14
2.5	SCHEDULE FOR COMPLETION OF TASKS.	14
2.6	THE SUPPORT OR INPUTS TO BE PROVIDED BY THE BUREAU	15
	SCHEDULE III-ELIGIBILITY & PREQUALIFICATION CRITERIA	15
3.1	PREQUALIFICATION CRITERIA	15
3.2	CRITERIA FOR TECHNICAL EVALUATION	16
	SCHEDULE IV EVALUATION OF BIDS	17
4.1.1	PRELIMINARY EXAMINATION OF BIDS - DETERMINING RESPONSIVENESS	17
4.1.2	INFIRMITY OR IRREGULARITY OR NON-CONFORMITY - SUBSTANTIVE OR MINOR	17
4.1.3	CLARIFICATION OF BIDS AND SHORTFALL DOCUMENTS	18
4.1.4	CONTACTING THE BUREAU DURING EVALUATION	18
4.2	RIGHT TO ACCEPT ANY BID AND TO REJECT ANY OR ALL BIDS	18
	SCHEDULE VI	19
	ANNEXURE I PRE-BID QUERY FORMAT	20
	ANNEXURE II UNDERTAKING REGARDING MULTIPLE TABLEAUX AS PER THE REQUIREMENT OF MINISTRY OF DEFENCE	21
	ANNEXURE III FINANCIAL BID FORMAT	22
	ANNEXURE IV CONCEPT NOTE AND INTRODUCTION TO THE BUREAU AND ITS KEY ACTIVITIES	29
	ANNEXURE V GIST OF THE PROVISIONS OF RULE 144 (XI) OF GENERAL FINANCIAL RULES 2017	34
	ANNEXURE-VI DECLARATION REGARDING BLACKLISTING, LITIGATIONS OR CRIMINAL	35

	OFFENCE OR CONVICTION ON LETTERHEAD OF THE BIDDER	
	ANNEXURE VII DECLARATION REGARDING TERMINATION OF PREVIOUS CONTRACT AND CONFLICT OF INTEREST ON LETTERHEAD OF THE BIDDER	36
	ANNEXURE VIII DECLARATION FOR ABIDING BY THE CODE OF INTEGRITY IN PUBLIC PROCUREMENT (CIPP)	37
	ANNEXURE IX INTEGRITY PACT	38

## **DISCLAIMER**

1. The information contained in this Expression of Interest (EoI) is for engagement of agency for conceptualizing, fabricating and displaying a Tableau during Republic Day Parade of India 2022
2. The EoI document is not a recommendation, offer or invitation to enter into a contract, agreement or any other arrangement, in respect of the services. The provision of the services is subject to observance of selection process and appropriate documentation agreed between the Bureau and any contractor as identified by the Bureau, after completion of the selection process as detailed in this document.
3. No contractual obligation whatsoever shall arise from the tendering process unless and until a formal agreement is executed between the Bureau, through its duly authorised officer and the successful bidder (the bidder whose bid has been accepted by the Bureau).
4. The purpose of this EoI is to provide the Bidder(s) with information to assist the formulation of their proposals. This EoI does not claim to contain all the information each bidder may require. Each bidder should conduct their own study or investigations and analysis and should check the completeness of the information in this EoI and where necessary obtain independent advice. The Bureau shall not incur any liability, whatsoever, with regard to the completeness of the information contained in the EoI that the bidder may require for submission of the bid. The Bureau reserves the right to amend any condition of the EoI through publication of a Corrigendum, besides rejection of any or all the bids received, if the Competent Authority of the Bureau decides so.
5. The Bureau may in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this EoI. Such revisions to the EoI or amended EoI, if any, will be made available on website the Bureau and Central Public Procurement (CPP) Portal.
6. The Bureau will not be responsible for any delay in receiving the proposals. The issue of this EoI does not imply that the Bureau is bound to select a bidder or to appoint the selected bidder, as the case may be, for the services and the Bureau reserves the right to accept or reject any or all of proposals submitted in response to EoI document at any stage without assigning any reasons whatsoever. The Bureau also reserves the right to withhold or withdraw or even cancel the process at any stage with intimation to all who submitted bids.

## NOTICE FOR REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

1. Bureau of Indian Standards (The Bureau) is the National Standards Body of India under the aegis of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution established under Bureau of Indian Standards Act 2016.
2. The Bureau invites Expression of Interest from eligible and qualified bidders on or before the scheduled bid submission closing date and time, through the CPP Portal (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app> portal) for delivery of the services as detailed in this EoI document.
3. The shortlisted bidders through the process of EoI as detailed in the EoI document shall only be issued Request for Proposal (RFP) document which shall be based on two bid system comprising technical and financial bids from the shortlisted bidders on or before the scheduled bid submission closing date and time, through the CPP Portal (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app> portal) for entering into contract for delivery of services as detailed in the RFP document.
4. The Bureau is completing 75 years of its existence and serving the nation through Standardization, Conformity Assessment and other significant activities. As a part of celebrating this proud occasion, it has been decided that the Bureau may make a proposal to have its Tableau during Republic Day Parade of India 2022. To achieve this objective, the Bureau intends to engage an experienced agency capable of conceptualizing, fabricating and displaying a Tableau of the Bureau during Republic Day Parade 2022. Expression of Interest is invited from reputed, eligible and qualified agencies for the same. The agency must be capable of showcasing through the Tableau the milestones achieved by the Bureau through its key activities, in its journey from establishment, till date. The brief details of EoI are given below:

1)	Eligibility Criteria	As per para 3.1 of the EoI
2)	Validity of the Contract	Till the actual fabrication and presentation of the Tableau during the Republic Day Parade 2022 and associated works.
3)	Availability of the EoI document	(a) CPP Portal <a href="http://www.eprocure.gov.in">www.eprocure.gov.in</a> (b) Website of the Bureau <a href="http://www.bis.gov.in">www.bis.gov.in</a> (for reference only)
4)	Mode of submission	Online only through CPP Portal
5)	Bid system and Envelope	Two bid system (Technical and Financial bids in two separate envelopes) at RFP stage
6)	Validity of bids	90 days from the date of submission of the bids
7)	Cost of the EoI	Nil

5. The Bureau reserves the right to accept the whole, or part of or reject any or all bids without assigning any reasons and to select the bidder(s) who best meet the interest of the Bureau.

## Critical Date Sheet

Sl.No.	Event	Date or Place
i.	Date of uploading EoI on Central Public Procurement Portal	14 July, 2021
ii.	Document Download Start Date	14 July, 2021
iii.	Document Download Closing Date	27 July, 2021
iv.	Clarification Start Date	15 July, 2021
v.	Clarification End Date	19 July, 2021
vi.	Pre-Bid Meeting	20 July, 2021 at 11.00 hrs, (Virtual/Physical)
vii.	Bid Submission Start Date	15 July, 2021 at 1000 hrs.
viii.	Bid Submission End Date	27July, 2021 at 1500 hrs.
ix.	Opening of bids	28 July, 2021 at 1500 hrs.

## SCHEDULE – I INFORMATION TO BIDDERS

### 1.1 DEFINITIONS

- i. **“The Bureau”** shall mean the Bureau of Indian Standards established under Bureau of Indian Standards Act, 2016.
- ii. **“Competent Authority”** shall mean the Director General of the Bureau.
- iii. **‘Contractor’** shall mean selected bidder or implementing agency under this EoI .
- iv. **“Expert Committee”**- shall mean Expert Committee of Ministry of Defence constituted for the purpose of evaluating the proposals of Tableaux received from various States or UTs or Ministries or Departments etc.
- v. **“Head of the Procuring Organisation”** shall mean the Director General of the Bureau.
- vi. **“Letter of Acceptance”** shall mean the written communication to the successful bidder containing information that his bid has been accepted by the Competent Authority of the Bureau.
- vii. **“Notice of Award”** shall have the same meaning as for the words “Letter of Acceptance.”
- viii. **“Expression of Interest (EoI)”** shall mean a document issued by the Bureau), including any amendment thereto, that sets out the terms and conditions of the given procurement and includes the invitation to bid. A Standard (Model) Bidding Document is the standardised template to be used for preparing Bidding Documents after making suitable changes for specific procurement. The term ‘EoI’ shall have the same meaning for the purpose of the resultant contract through this invitation as for the words “Tender Document” or “Request for Proposal (RFP)” in the GCC or elsewhere in this document.
- ix. **“Successful bidder”** shall mean the bidder whose proposal has been selected and Letter of Acceptance has been issued by the Bureau for implementing the work defined in this EoI and amendment thereto.

### 1.2 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

<i>Abbreviation or Acronym</i>	<i>Full Form</i>
<b>EOI</b>	Expression of Interest
<b>RFP</b>	Request for Proposal
<b>BSD</b>	Bid Security Declaration
<b>PPP (MII)</b>	Public Procurement (Preference to Make in India) Order
<b>IPR</b>	Intellectual Property Rights
<b>CPP</b>	Central Public Procurement
<b>EMD</b>	Earnest Money Deposit
<b>GST</b>	Goods & Service Tax
<b>PAN</b>	Permanent Account Number

<b>MSEs</b>	Micro and Small Enterprises
<b>QCBS</b>	Quality and Cost Based Selection
<b>RTGS</b>	Real-Time Gross Settlement
<b>FDR</b>	Fixed Deposit Receipt
<b>NEFT</b>	National Electronic Funds Transfer
<b>IFSC</b>	Indian Financial System Code
<b>TAN</b>	Tax Deduction and Collection Account Number
<b>SLA</b>	Service Level Agreement
<b>SPOC</b>	Single Point of Contact
<b>PSU</b>	Public Sector Undertaking
<b>GFR</b>	General Financial Rules
<b>GCC</b>	General Conditions of Contract
<b>SCC</b>	Special Conditions of Contract
<b>INR</b>	Indian Rupee
<b>MoD</b>	Ministry of Defence
<b>DPIIT</b>	Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry
<b>FY</b>	Financial Year

### 1.3 PROCEDURE OF ONLINE BID SUBMISSION

#### 1.3.1 ONLINE BID SUBMISSION

- i. The complete Bid will be received **online through the Central Public Procurement Portal (CPP Portal) (www.eprocure.gov.in) only.**
- ii. The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal. More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.
- iii. Bidder should be responsible for registering his company at Central Public Procurement Portal and seeking all necessary approvals required to upload the bid.
- iv. The Bureau reserves the right to amend the document, tentative schedule and critical dates. It is the sole responsibility of prospective bidders to go through Central Public Procurement Portal or the Bureau Website from time to time for any updated information.

#### 1.3.2 REGISTRATION ON CPP PORTAL

- i. Bidders are required to enrol on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) by clicking on the link “Online bidder Enrolment” on the CPP Portal which is free of charge.
- ii. As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.



- iii. Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.
- iv. Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class II or Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify or nCode or eMudhra etc.), with their profile.
- v. Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.
- vi. Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID or password and the password of the DSC or e-Token.

### **1.3.3 SEARCHING FOR EOI DOCUMENT**

- i. There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.
- ii. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents or tender Annexes. These tenders can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS or e-mail in case there is any corrigendum issued to the EoI.
- iii. The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender; in case they want to obtain any clarification or help from the Helpdesk.

### **1.3.4 PREPARATION OF BIDS**

- i. Bidder should consider any corrigendum published on the EoI before submitting their bids.
- ii. Please go through the tender advertisement and the EoI carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.
- iii. Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the EoI or Annex and generally, they can be in PDF or XLS or RAR or DWF or JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
- iv. To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

### **1.3.5 SUBMISSION OF BIDS**

- i. Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.
- ii. The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the EoI.
- iii. Bidder should submit a Bid Security Declaration in the prescribed format as per the instructions specified in the EoI.
- iv. The server time which is displayed on the bidders' dashboard will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.
- v. All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128-bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further, this key is subjected to asymmetric encryption using buyers or bid openers public keys. Overall, the uploaded EoI becomes readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- vi. The uploaded EoI becomes readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- vii. Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking "Freeze Bid Submission" in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.
- viii. The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

### **1.3.6 ASSISTANCE TO BIDDERS**

- i. Any queries relating to the EoI and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender through CPP portal.
- ii. Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk Nos. 0120-4200462, 0120-4001002.

### **1.4 COST OF BID PREPARATION AND SUBMISSION**

The bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.

### **1.5 LANGUAGE OF BID**

The language of the Bid shall be in English or Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English or Hindi language. In case of any dispute, English version will prevail over Hindi version.

## 1.6 PRE-BID MEETING

A pre-bid meeting will be held on the date and time as given in the date sheet through VC virtual or physical mode, which will be communicated through the Bureau website to prospective bidders. Bidders may send their query in the format given in Annexure I up to two days prior to the pre-bid meeting. The queries shall be addressed in the meeting and if need is felt, necessary corrigenda may be issued by the Bureau and extension of time may be allowed. No query shall be addressed thereafter.

## 1.7 PRE-QUALIFICATION ENVELOPE

i. The Pre-qualification envelope shall contain the following checklist along with Information or Documents as mentioned below. The checklist must be signed and sealed by the bidder.

### Checklist

Particulars	To be filled by Bidder			
1. Name of the Bidder				
2. Whether brief profile of the contractor is enclosed (Max 2-3 pages)				
3. Address of the Bidder	Tel.		Fax.	
4. Year of establishment				
5. Index of all documents listed at para 3.1	Whether enclosed-YES NO			
6.All documents listed at para 3.1 in the same sequence as of the index	Whether enclosed-YES/NO			
7. Power of Attorney or Board Resolution executed in favour of the signatory of the bid. In case of entities other than company or firm or LLP, authorisation from the Chief Executive on letterhead may be submitted.	Whether enclosed-YES/NO			
8. Undertaking as per Annexure II (Regarding fabrication of multiple Tableaux)	Whether enclosed-YES/NO			
9. Name, Designation and address of the officer to whom all references shall be made regarding this EoI.	Tel:	Mobile:	Fax:	Email:
10. A brief Note of 2-3 pages the comments of the bidder on the objectives and scope of the work or service projected in the EoI document. Bidders must not indicate their approach to the services or submit any curricula vitae of key personnel and comments on only objectives, scope of work and services projected and inputs deployable need to be indicated in this document.	Whether enclosed-YES/NO			

ii. The Bureau reserves the right to solicit additional information from bidders.

## **1.8 PERIOD OF CONTRACT**

The Contract shall remain valid till the completion of all contractual obligations as per the Terms of Reference of the RFP to be issued to the shortlisted bidders viz. actual fabrication and presentation of the Tableau during the Republic Day Parade 2022, and associated works [like dismantling of the tableau and safe disposal of the waste generated (if any) etc.]

## **1.9 AMENDMENT**

At any time before the submission of bids, the Bureau may amend the EoI document by issuing an addendum or corrigendum in writing or by announcing it through e-procurement portal and its website. The addendum or corrigendum shall be binding on all the bidders. To allow the bidder reasonable time in which to take an amendment into account in their bids, the Bureau may, if the amendment is substantial, extend the deadline for the submission of bid.

## **1.10 CONFLICT OF INTEREST**

### **1.10.1 During Bidding Process**

i. A participant in this Tender Process shall be considered to have a conflict of interest with one or more participants in this Tender Process, if:

- (a) They have controlling partner (s) in common; or
- (b) They receive or have received any direct or indirect subsidy or financial stake from any of them; or
- (c) They have the same legal representative or agent for purposes of this Bid; or
- (d) They have relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder; or
- (e) they participate in more than one Bid in this tender process. Participation in any capacity by a bidder (including participation of a bidder as sub-contractor in another bid or vice-versa) in more than one Bid shall result in the disqualification of all bids in which the parties are involved. However, this does not limit the participation of a firm as a sub-contractor in more than one bid, if subcontracting is specifically allowed in the tender document; or
- (f) a bidder or any of its affiliates was associated as a consultant or in any other capacity in the preparation of the Detailed Project Report or feasibility report or Terms of Reference (ToR) or Schedule of Requirements of the Service Assignment that is the subject of the Bid;
- (g) In case of a holding company having more than one independent manufacturing units or more than one unit having common business ownership or management, only one unit should quote. Similar restrictions shall apply to closely related sister companies.
- (h) Bidder's sister or Associated or Allied concern(s) participating or applying against the same tender, shall lead to disqualification of bidders. Sister or Associated or Allied concern means a company, society, partnership firm or proprietorship firm having one or more common persons as Director or Partner or Member or Owner.

- (i) Bidders must proactively declare in their bids such sister or allied or associated companies and holding or common business ownership or management in same or similar line of business or any other situations as mentioned above.

### **1.10.2 During Contract Execution**

i. The Contractor shall hold the Bureau's interest's paramount at all times, strictly avoid conflicts with other assignment or jobs or their own corporate interest and act without any consideration for future work.

ii. The contractor has an obligation to disclose to the Bureau any situation of actual or potential conflict that impacts its/his capacity to serve the best interest of the Bureau. Failure to disclose such situations may lead to the disqualification of the contractor or termination of his contract during execution of the assignment.

iii. Without limitation on the generality of the foregoing, Contractor, and any of their affiliates, shall be considered to have a conflict of interest and shall not be appointed, under any of the circumstances set forth below:

- (a) A Contractor including its affiliates shall not be hired for any assignment or job that, by nature, may be in conflict with another assignment or job of the Contractor to be executed for the same or for another Employer.
- (b) A Contractor that has a business or family relationship with a member of the Bureau staff who is directly or indirectly involved in any part of the project shall not be awarded the Contract, unless the conflict stemming from this relationship has been resolved in a manner acceptable to the Bureau throughout the selection process and the execution of the Contract. Contractor have an obligation to disclose any situation of actual or potential conflict that impacts their capacity to serve the best interest of the Bureau, or that may reasonably be perceived as having this effect. Any such disclosure shall be made as per the forms of technical proposal provided herewith. If the Contractor fails to disclose said situations and if the Bureau comes to know about any such situation at any time, it may lead to the disqualification of the Contractor during bidding process or the termination of its contract during execution of the assignment.

### **1.11 CONDITIONAL BIDS**

Conditional bids shall be rejected. Bids not fulfilling any of the stipulations and or gives evasive information/ reply against any such stipulations, shall be liable to be ignored and rejected. Bids submitted by any other means than those specified in EoI shall be ignored.

### **1.12 SUBCONTRACTING**

Subcontracting shall not be allowed.

## **SCHEDULE – II DESCRIPTION OF SERVICES- OBJECTIVES AND SCOPE OF WORK**

### **2.1 Guidelines of Ministry of Defence**

A gist of the relevant guidelines issued by the Ministry of Defence last year (i.e. 2020, for Republic Day parade 2021) for selection of the Tableau is given in Annexure III. Bidders are advised to go through the same thoroughly to understand the requirements indicated therein so as to ensure that the guidelines are adhered to, for preparation of the concepts and sketches, 3D model, followed by actual execution and presentation of the Tableau during the parade. The guidelines to be issued in 2021 (i.e. for Republic Day Parade 2022) are expected in the month of July 2021. The selected bidder must regularly visit the website of Ministry of Defence to ensure that any changed requirements or updates are taken care of.

### **2.2 Concept Note of the activities of the Bureau**

The bidders are further requested to ensure thorough understanding about the Bureau such as its coming into existence, developments thereafter, its functions, milestones achieved etc. as per the information given in the Concept Note in Annexure IV.

**2.3** The theme for the Bureau's Tableau is "BIS- In service of the nation since 1947."

### **2.4 Tasks to be carried out by the bidder**

The Bureau is completing 75 years of its existence and serving the nation through Standardization, Conformity Assessment and other significant activities. As a part of celebrating this proud occasion, it has been decided that the Bureau may make a proposal to have its Tableau during Republic Day Parade of India 2022. To achieve this objective, the Bureau intends to engage an experienced agency capable of conceptualizing, fabricating and displaying a Tableau of the Bureau during Republic Day Parade 2022. The agency must be capable of showcasing through the Tableau the milestones achieved by the Bureau through its key activities, in its journey from establishment, till date.

### **2.5 Schedule for completion of tasks.**

The tentative timelines are indicated below:

<b>Sl No.</b>	<b>Milestones</b>	<b>Timeline</b>
1	Submission of the final sketches or designs in physical as well as in digital form i.e in virtual reality on pen-drive or CD showing the various components displayed from different angles to the Bureau for onward submission to the Expert Committee of Ministry of Defence (MoD)	At least 10 days prior to the last date of submission of the Sketch to the Expert Committee
2	Submission of the final 3D Model to the Bureau for onward submission to the Expert Committee	At least 10 days prior to the last date of submission of the 3D Model to the Expert Committee
3	Requirements as intimated by the Expert Committee	At the earliest maximum upto three days or the time-limit given by the Expert Committee whichever is earlier
4	Ensuring completeness of the preparation of Fabrication of the Tableau for the Republic Day Parade 2022	1 Day prior to the Full Dress Rehearsal for Republic Day Parade

## 2.6 The Support or Inputs to be provided by the Bureau

- 1) The Bureau shall suggest necessary modifications in the sketch or design or 3D Model submitted by the contractor in timely manner, as deemed appropriate by the Bureau.
- 2) The Bureau shall ensure release of the timely payments as and when fallen due as per the agreed terms.
- 3) The Bureau shall have absolute right to suggest the quality, inputs, aesthetic creative and technology driven delivery of the final service i.e. fabrication of the Tableau in the interest of the work. The bidder shall be bound to carry out all such modifications suggested.

## Schedule III-ELIGIBILITY & PREQUALIFICATION CRITERIA

### 3.1 Prequalification Criteria

i. The invitation for EoI is open to all bidders who qualify the Pre-qualification criteria as given below:

Sl.No.	Criteria	Supporting document
1)	Bidder should be a natural person or private entity or public entity (legally and financial autonomous Government owned enterprises). <b>Joint Venture or Consortium is not permitted.</b>	Self-attested copy of Certificate of Incorporation of the company. OR Self-attested copy of Certificate of Registration OR Self-attested copy of Bye-Laws for Public Entities
2)	The Bidder should have successfully provided at least 2 Tableaux during the last five years (26 January 2017 onwards) in Republic Day Parade of India for Central Government, State Govt., Union Territory, Autonomous Body or PSU of the value of minimum Rs. 30 Lacs (Rupees Thirty Lacs) each.	(a) Self-attested copies of the work order along with the completion certificates for at least two such tableaux. (b) The bidder shall also provide list containing details of all tableaux executed from 26 January 2017 onwards along with the details of the client Department and award (mentioning 1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> or 3 <sup>rd</sup> ) received from the Government for each Tableau, if any.
3)	<b>Compliance of Rule 144 (xi) of General Financial Rules and Orders issued thereunder:</b> Any bidders from such countries which share land border with India will be eligible to bid only if the bidder is registered with the Competent Authority as specified by the Government of India. A gist of the relevant clauses of the said rule and orders are given in Annexure V which may be referred to. However, the bidders must check Rule 144 (xi) of GFR and Orders issued thereunder to be sure about their eligibility. In case the bidder is from such country, the evidence of valid registration must be submitted along with the above certificate.	Certificate to the effect confirming compliance of Rule 144 (xi) of General Financial Rules on the letter head in the following format “I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India; I certify that this bidder is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority. I hereby certify that this bidder fulfils all requirements in this regard and is eligible to be considered.” In case of agencies registered with the Competent Authority, a valid registration Certificate shall be enclosed.
4)	Only Class I & Class II Local Suppliers as defined in	Certificate as per para 9 (a) of Public Procurement

	the Public Procurement (Preference to 'Make in India') Order shall be eligible to bid and Non-Local Suppliers shall not be eligible to bid. Bidders must visit the website of Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Government of India to be aware of the updated rule position. Minimum Local Content – The 'local content' requirement to categorize a supplier as 'Class-I local supplier' is minimum 50%. For Class-II local supplier', the minimum 'local content' requirement is 20%.	(Preference to Make in India) Order 2017 (latest being dated 16.09.2020*).
5)	(a) The bidder should have annual turnover of Rupees 1 crore each during last 3 financial years (FY 17-18, FY 18-19, FY 19-20) from event management activities. (b) In case of Micro and Small Enterprises (MSEs) and Startups, the turnover requirement will be Rs.75 lakhs during each of last 3 FYs. <b>Bidders may note that Turnover is not being required for the FY 20-21 to enable maximum bidders to participate in the tendering process as several businesses were adversely impacted due to spread of the Covid-19 pandemic.</b>	(a) Self-attested copy of audited Profit & Loss Account (P&L); OR Certificate from the statutory auditor or Chartered Accountant. In case, the P&L A/c does not depict specifically the turnover from event management activities separately, a certificate from statutory auditor or Chartered Accountant depicting the same may be submitted. (b) Self-attested valid certificate of registration as Micro and Small Enterprise (MSE) or Startup from appropriate authority.
6)	It should be registered with the Goods & Services Tax (GST) Authorities and hold a valid PAN.	Self-attested copy of Goods & Services Tax Registration certificate. If opted for Composition Scheme, the same may be indicated. Self-attested copy of PAN card.
7)	It should not have been blacklisted, should not have been found guilty of any criminal offence by any Court of law.	Undertaking on letter head in the format given at Annexure VI
8)	It should not have its previous contract terminated by the Procuring Organisation; should not have a conflict of interest which substantially affects fair competition	Undertaking on letter head in the format given at Annexure VII
9)	It must comply with the Code of Integrity in Public Procurement (CIPP)	Undertaking on letter head in the format given at Annexure VIII
10)	It must submit the signed and stamped Integrity Pact (IP)	Integrity Pact in the format given at Annexure IX

\*can be found at link

<https://dipp.gov.in/sites/default/files/PPP%20MII%20Order%20dated%2016%2009%202020.pdf>

ii. If a bidder furnishes wrong or misleading data, statement(s) etc. about pre-qualification acceptability of the Services offered by it, its bid shall be liable to be ignored and rejected in addition to other remedies available to the Bureau in this regard.

### 3.2 CRITERIA FOR TECHNICAL EVALUATION

i. Those bidders who pre-qualify based on the documents submitted by them as per the requirements given at para 3.1 above, shall be issued the Request for Proposal Document.



## **Schedule IV EVALUATION OF BIDS**

**4.1** Evaluation of bids shall be based only on the criteria or conditions included in the EoI . No other criteria or condition shall form the basis of this evaluation.

### **4.1.1 Preliminary Examination of Bids - Determining Responsiveness**

A substantively responsive bid is one which is complete and conforms to essential and important terms, conditions, and requirements of the EoI document, without substantive deviation or reservation or infirmity. Only substantively responsive bids shall be considered for further evaluation. If a bid is not substantively responsive, it shall be considered as unresponsive, rejected, and not considered for further evaluation. The following are some of the important illustrative (not exhaustive) aspects, for which a bid shall be declared unresponsive and ignored:

- i. The bid is not in the prescribed format or is unsigned or not signed as per the stipulations in the bid document.
- ii. The bidder is not eligible to participate in the bid as per laid down eligibility criteria;
- iii. The Services offered are not eligible as per the provision of this EoI .
- iv. The bidder has quoted conditional bid or more than one bids or alternative bids.
- v. The bid validity is shorter than the required period.
- vi. The bid departs from the essential requirements specified in the bidding document;
- vii. The bidder has not quoted for the entire services as specified in that schedule.
- viii. Non-submission or submission of illegible scanned copies of stipulated documents or declarations shall render the bid non-responsive. Also, in case discrepancies are observed between scanned uploaded documents and the copies or original documents submitted physically (if so required by the Bureau at any stage whether or not such requirement is mentioned in the EoI ) then the bid shall be declared as unresponsive. In case it is determined to be violation of Code of Integrity in Public Procurement or Integrity Pact, punitive actions shall also be taken.

### **4.1.2 Infirmity or Irregularity or Non-Conformity - Substantive or Minor**

(1) If during evaluation, the Bureau finds any infirmity or irregularity or non-conformity in any Bid, it shall be considered as a substantive deviation as per following norm and the rest shall be considered as Minor deviation:

- (a) which affects in any substantive way the scope, quality, or performance standards of the Services;
- (b) which limits in any substantive way, inconsistent with the EoI Document, the Bureau's rights as procuring entity or the bidder's obligations under the Contract; or

(c) whose rectification would affect unfairly the competitive position of other bidders presenting substantively responsive Bids.

(2) Decision of the Bureau shall be final in this regard. Bids with substantive deviations shall be considered as unresponsive and shall be rejected and not evaluated further.

(3) The Bureau reserves the right to accept or reject bids with any minor deviations. Wherever necessary, the Bureau shall convey its observation as per sub- clause below, on such ‘minor’ issues to the bidder by registered or speed post or electronically etc. asking the bidder to respond by a specified date. If the bidder does not reply by the specified date or gives evasive reply without clarifying the point at issue in clear terms, that Bid shall be liable to be ignored.

#### **4.1.3 Clarification of Bids and shortfall documents**

i. During evaluation of bids, the Bureau may, at its discretion, but without any obligation to do so, ask the bidder for clarification of its Bid by a specified date. The clarification should be answered by the bidder within that specified date. The request for and the clarification shall be in writing and no change in prices or substance of the Bid shall be sought, offered, or permitted that may grant any undue advantage to such bidder.

ii. The Bureau reserves its right to, but without any obligation to do so, to seek any shortfall information or documents only in case of historical documents which pre-existed at the time of the bid opening and which have not undergone change since then and does not grant any undue advantage to any bidder. There is a provision on the portal for requesting Short-fall documents from the bidders. The system allows to take the shortfall documents from any bidders only once after the technical bid opening.

#### **4.1.4 Contacting the Bureau during evaluation**

From the time of submission of tender to the time of awarding the Contract, no bidder shall contact the Bureau on any matter relating to the submitted Bid. If a bidder needs to contact the Bureau for any reason relating to this tender or its Bid, it should do so only in writing. Any effort by a bidder to influence the Bureau during processing of bids, evaluation, Bid comparison or award decisions shall be treated as Corrupt & Fraudulent Practices, and shall result in the rejection of the bidders' Bid.

#### **4.2 Right to accept any Bid and to reject any or all bids**

The Bureau reserves the right to accept or reject any or all bids; cancel the tender process and re-invite the bids at any time prior to the award of Contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligation to inform the affected bidder or bidders of the grounds for the Bureau's action.

## Schedule VI

### Annexures

ANNEXURE NUMBER	PARTICULARS
I	PREBID QUERY FORMAT
II	UNDERTAKING REGARDING MULTIPLE TABLEAUX AS PER THE REQUIREMENT OF MINISTRY OF DEFENCE
III	GUIDELINES ISSUED BY MINISTRY OF DEFENCE IN THE YEAR 2020
IV	CONCEPT NOTE AND INTRODUCTION TO THE BUREAU AND ITS KEY ACTIVITIES
V	GIST OF THE PROVISIONS OF RULE 144 (XI) OF GENERAL FINANCIAL RULES 2017
VI	DECLARATION REGARDING BLACKLISTING, LITIGATION AND CRIMINAL OFFENCE ETC.
VII	DECLARATION REGARDING TERMINATION OF PREVIOUS CONTRACT AND CONFLICT OF INTEREST
VIII	DECLARATION FOR ABIDING BY THE CODE OF INTEGRITY IN PUBLIC PROCUREMENT (CIPP)
IX	INTEGRITY PACT

### ANNEXURE I

#### Pre-Bid Query Format

**Ref: EoI Ref. No. <xxx> dated <dd or mm or yyyy>**

Name of the Bidder: .....

Contact Number and Address of the Bidder: .....

Sl.No.	Para/Clause Number of the Document	Page Number	Query	Remarks

## ANNEXURE II

### **Undertaking regarding Multiple Tableaux as per the requirement of Ministry of Defence**

**(To be given on Company Letter Head)**

I/We hereby declare that in the event of our firm or company being selected as the successful implementing bidder for the Bureau, our firm or company shall:

(a) not be involved in designing or fabricating any other Tableau for any other State or Ministry etc.

OR

(b) ensure that the tableaux for other States or Ministries etc. shall be designed or fabricated by it in such a manner so that it maintains quality and **avoid monotony** in the Parade.

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

ANNEXURE-III

GUIDELINES ISSUED BY MINISTRY OF DEFENCE IN THE YEAR 2020

REPUBLIC DAY MATTER

No. 1(III)/1/2020/D(Cer)

Government of India  
Ministry of Defence

Room No. 1, South Block,  
New Delhi, the July, 2020.

To

The Chief Election Commissioner of India, Election  
Commission of India,  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-01.

---

2.1.1 THE VICE CHAIRMAN,  
NITI AYOJ, NITI AYOJ/YOJANA  
BHAWAN, SANSAD MARG, NEW  
DELHI-01.

Subject: Republic Day Celebrations, 2021      Selection of Tableaux regarding.

Sir,

Every year, a select number of tableaux from State Governments/UT Administrations/Central Ministries/Departments participate in the Republic Day Parade in New Delhi. This letter initiates the process of inviting tableau proposals for participation in the Republic Day Parade 2021. Relevant guidelines for the purpose are enclosed at Annexure I. It may be noted that participating in the selection/shortlisting process with a proposal for consideration by an Organization will be deemed to be the acceptance of the Guidelines by the said proposing entity.

2. Selection Process of tableau an elaborate and time-consuming exercise. Ministry of defence constitutes a Committee of distinguished persons drawn from various fields of the arts to help in shortlisting the best proposals. This necessitates that the selection

process commences well in advance.

3. In view of the time-constraints, this Ministry will be able to include only a limited number of proposals. For encouraging the participants, the best three tableaux are given trophies by this Ministry.

4. Willingness of the Commission may be conveyed along with well conceptualized proposals and brief write-ups to this Ministry by 31<sup>st</sup>\* August 2020.

Yours faithfully,



(Sa  Singh)  
Joint Secretary to the Govt. of India

Joint Secretary to the Govt. of India

Tele: 2301 1862.

Copy to:-

 D(IT), MoD

With the request to upload the same on MoD's website.

SOC(17)

 27/07/2020

---

## 2.2 GUIDELINES FOR PREPARATION OF TABLEAUX PROPOSALS FOR PARTICIPATION IN THE REPUBLIC DAY PARADE-2021.

### 1. Suggestive List of Themes

- i) Any important episode from the history of the State/Union Territory.
- ii) Festivals Celebrated.

### III) CULTURAL/ARCHITECTURAL HERITAGE INCLUDING ANY ASPECT OF THE LIFE OF THE PEOPLE.

- iv) Any important social and economic development scheme, project or achievement of outstanding nature which merits a display in the National Parade.

### V) ENVIRONMENT.

- vi) Vision for the future.

### 2. Selection Process

- (i) The tableaux proposals received from various organizations/agencies are evaluated in a series of meetings of the Expert Committee consisting of prominent persons in the field of art, culture, painting, sculpture, music, architecture, choreography, etc. In the first phase of selection, the sketch/design of the proposals are scrutinized and suggestions, if considered necessary, are given to carry out modifications in the sketch/design. Once the sketches/designs are approved by the Committee, thru participants are asked to come up with three-dimensional models of their proposals. However, entering into the model stage itself does not mean selection. The models are thereafter examined by the Committee for final selection depending upon various considerations. Not more than one tableau from an organization participates in the Parade. Adequate time is given to the concerned agencies to make arrangements for attending the meetings of the Expert Committee. Non-attendance in any meeting means withdrawal and concerned agency will not be invited in subsequent meetings. All cost for attending the meetings is to be borne by the concerned agency. All interaction with the members of the Committee will be made by the official representative of the organization concerned. The artists/designers, etc. may accompany the official representative to suitably take note of the suggestions given by the Committee to carry out modifications in their respective sketch/design/model. They will, however, not directly interact with the members of the Expert Committee unless they are specifically authorized by the Committee to do so to explain any specific point.

(ii) This Ministry does not prescribe any firm/fabricator for design & construction of tableau for participating in Republic Day Parade. The State/UT/Ministry/Department may engage/appoint any firm/fabricator for this purpose on their own. However, to maintain quality and avoid monotony in look/design of the tableaux, it is suggested that concerned State/UT/Ministry/Department may consider to evolve suitable mechanism so that the firm /fabricator engaged/appointed for the purpose may not be involved in designing/fabricating multiple tableaux for the Parade.

(iii) It is highlighted that selection of Tableaux passes different stages starting from initial appreciation of sketch/design and the themes brought forward by the States/UTs/Ministries/Departments followed by a three dimensional model which culminates into the selection of the actual model by Expert Committee through a series of interactions where all aspects of the tableaux are discussed threadbare. The selection depends upon a combination of factors including but not limited to visual appeal, impact on the masses, idea/theme of the tableaux, degree of detailing involved in the tableaux, music accompanying the tableaux etc. The selection process normally extends over six to seven rounds of meetings on different days with some elimination and short listing at each stage. Only the shortlisted States/UTs/Ministries/Departments in any given round of selection are informed about the next round of selection. Mere advancement from one stage to another does not entitle any participating State/UT/Ministry/Department for movement to another further round or the final selection, till it is confirmed. In the event of final selection also, there may be a possibility of a particular tableaux not being able to participate in the final parade, if it has not been created in terms of the final approved version during selection rounds.

### 3. Preparation of Sketch/Design

The sketch/design drawn on a scale of 1': 1" should be simple, colourful, easy to comprehend and should avoid statistical data and unnecessary details. It should be able to convey, whatever it presents, by itself and should not require any explanation, writing or elaboration. Writing or use of logos on tableaux is not allowed except the name of States/UTs presenting which is allowed in Hindi in the front, in English on the back and in Regional language on the sides of the tableau. Similarly, in case of Ministries/Departments and other agencies, name of the Ministry/Department/organization is to be given in Hindi in the front and in English on the back. Designs in virtual reality in the form of CD showing the various components displayed from different angles, can also be presented.



---

#### 4. PREPARATION OF MODELS

After the approval of the proposed sketch/design by the Expert Committee in its preliminary meetings, three dimensional model of the proposed tableau would be prepared on the lines of the suggestions given by the Committee for further inspection. Final approval for participation would be accorded only after the models of the tableaux are finally selected by the Committee.

---

#### 5. POINTS TO BE KEPT IN VIEW WHILE DRAWING UP THE PROPOSAL

(i) One tractor and one trailer upon which a tableau would be fabricated, would be provided by the Ministry of Defence free of charges.

(ii) No **additional** tractor, trailer or other types of vehicles would be allowed to be used in the tableau. This aspect should be kept in mind while preparing the designs of the tableau proposals to be presented before the Central Expert Committee.

(iii) There is no objection to the use of vehicles other than tractor and trailers for fabrication of tableaux to give them a different look. But these vehicles will have to be arranged by the sponsoring authorities themselves. Under no circumstance, the total number of vehicles used in a tableau or the total number of distinguishable mobile components of a tableau would be more than two.

(iv) As far as possible, there should be some movement, sound and animation on the tableaux.

(v) The number of performers on the trailer would not be more than 10 persons. No performer is permitted to be on the tractor component of the tableau. Attractive ground element however can be considered on a limited number of tableaux only if it goes with the theme. These conditions are subject to modifications by MoD depending on the requirement of the tableau.

(vi) In case of tableaux on cultural, historical/traditional themes, the colours, designs, costumes, materials, etc. used should be authentic to present local flavour. The performers on the float or onground should also look to be authentic in case any cultural or traditional event is being depicted.

(vii) The sketch should clearly depict as to how the tractor pulling the tableau will be used as a part of the theme. Camouflaging the tractor should be in harmony with the main theme of the tableau. There should be a gap of about 6-7 feet between the tractor and the trailer or between two trailers for turning or manoeuvring. This should be taken into account while designing the tableau.

(viii) In case, a tableau is proposed to be integrated with a folk dance, it should be ensured that the selected dance is a genuine folk dance and the costumes and musical instruments are traditional and authentic. The tableau and the dance should also have thematic unity. The strength of the dance party, excluding those who are to perform on the tableau, should not exceed 25 persons. The video clippings of the dance may also be sent along with the proposals.

(IX) STATE/UT MAY PREFERABLY ENGAGE ARTISTS PEI FORMING ON OR ALONG THE TABLEAU OF THE STATE/UT BELONGING TO THE CONCERNED STATE/UT ONLY, WHO WOULD HAVE A NATURAL FLAIR FOR THE PERFORMANCE CONSIDERING THE CRITICALITY OF THE EVENT. BONA FIDE OF ARTISTS ENGAGED BY THE STATE/UT/MINISTRY/DEPARTMENT MAY BE ASCERTAINED BY THE AUTHORISED GOVERNMENT OFFICIAL OF THE CONCERNED STATE/UT/MINISTRY/DEPARTMENT BEFORE DEPUTING THE ARTISTS' TEAM TO RASHTRIYA RANGSHALA CAMP.

(x) It is also suggested that State/UT/Ministry/Department may evolve their mechanism to ensure that the agency deployed for design/fabrication of the tableau remains associated with the job till finality to enable incorporating the originally conceived design along with the inputs of the Expert Committee from time to time.

#### 6. Dimensions

While preparing the sketches and subsequently, three dimensional models, the following approximate dimensions of the trailers and tractors, which will be supplied to them for the fabrication of the tableau, may be kept in view:

Trailer

Length	24' 8"
Width	8'
Height	4' 2"
Load carrying capacity	10 tons

The length, breadth and height of a single tableau should not exceed 45', 14' and 16' (from the ground level) respectively. If it is proposed to use any other vehicles under own arrangements, particulars thereof should be indicated in the proposal.

#### 7. Facilities to be provided by the Ministry of Defence During

the meetings of the Expert Committee, the facilities such as a PC, LCD Projector, DVD Player and an overhead projector would be made available by the Ministry of Defence. Should there be any other support requirements, the Ministry may be informed in advance.

8. Last date for conveying willingness alongwith  
5 SUBMISSION OF SKETCH/DESIGN FOR  
PARTICIPATION:

---

5.1.1 31<sup>ST</sup> AUGUST, 2020.

S++

## **ANNEXURE IV**

### **Concept Note and Introduction to the Bureau and its Key Activities**

In the twilight years of British rule in India, when the country was faced with the gigantic task of building up the industrial infrastructure, Department of Industries and Supplies issued a memorandum on 03 September 1946, formally announcing the setting of an organization called the “**Indian Standards Institution**”. The Indian Standards Institution (ISI) came into being on **the 06 January 1947** and in June 1947 Dr. Lal C. Verman took over as its first Director.

In the initial years, the organization concentrated on Standardization activity. To provide the advantages of standardization to common consumers, the Indian Standards Institution started operating the Certification Marks Scheme under the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952. The Scheme, which was formally launched by ISI in 1955-56, enabled it to grant licences to manufacturers producing goods in conformity with Indian Standards and to apply ISI Mark on their products. To meet the requirements of the Certification Marks Scheme, the nucleus of a laboratory was started in 1963. While the product certification was being operated under the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952, the formulation of standards and other related work were not governed by any legislation. A Bill with this objective was therefore introduced in the Parliament.

**Bureau of Indian standards (BIS)** thus came into existence, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, on 1 April 1987, with a broadened scope and more powers; taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile ISI. Through this change over, the government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of national standards.

The Bureau is a Body Corporate consisting of 25 members representing both Central and State governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies; with Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

Being the **National Standards Body**, the key activity of the Bureau is standardization. Standards development is a collaborative effort of the concerned stakeholders. Standardization also involves coordination between various bodies engaged in standards development in specific domains. Such cooperation and coordination is necessary throughout the standards development and implementation processes involving the government policy makers, manufacturing industries, service providers and the technical committees operating at national as well as international level.

The Bureau till date has developed more than **20,000 standards** on variety of products or services or method of tests or guidelines.

In this era of globalization, digitalization and converging technologies, the importance of International standards is increasing rapidly. As far as India’s participation in technical work at international level is concerned, The Bureau, on behalf of India is a participating member in 481

Technical Committees of ISO, which are of interest to India. Presently, the Bureau holds the Secretariat responsibilities of 11 Technical Committees of ISO. India also holds the convenorship for 26 working groups.

The Bureau is also responsible for the Indian National Committee of IEC since 1949, performing various responsibilities as the member body of the IEC Council. Presently, the Bureau is a participating member in 98 Technical Committees of IEC and holds convenorship of 12 working groups. A sizeable number of Indian Standards have been harmonized with ISO or IEC Standards to facilitate acceptance of Indian products in the international market.

As with formulation, implementation of standards is equally important, the Bureau has taken initiatives for creating awareness about the standards already formulated and strengthening stakeholder participation, Standardization Cells have been created by various Govt. Departments and Industry Associations.

The Bureau through its core activities of standardization and conformity assessment, has been benefiting the economy by providing safe, reliable and quality goods; minimizing health hazards to consumers; protecting the environment, promoting exports and import substitution; controlling proliferation of varieties and much more. The standards and certification schemes of the Bureau, apart from benefitting the consumers and industry, also support various public policies especially in areas of product safety, consumer protection, food safety, environment protection, building and construction, etc.

On 6<sup>th</sup> January 2022, the Bureau is proudly completing 75 glorious years of its existence. This is indeed an occasion not only for the Bureau but for the entire nation to celebrate. To depict the successful and grand journey of the Bureau in the service of nation, a tableau of the Bureau with the theme of '***BIS- In service of the Nation since 1947***' is envisaged to participate in the Republic Day Parade 2022.

Briefly, the key activities or achievements of the Bureau that can be displayed in the tableau are:

### **Standardization**

The Bureau of Indian Standards, erstwhile Indian Standards Institution (established in the year 1947) was established for the harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental thereto. A new Bureau of Indian Standards Act, 2016 which was notified on 22nd March 2016, has been brought into force with effect from 12 October 2017 that reinforces the activities of the Bureau in respect to standardization and certification of goods, articles, processes, systems and services.

To formulate standards through 16 division councils representing diverse area of economy and technology and services. The 16 Division Council are Chemical; Medical Equipment and Hospital Planning; Civil Engineering; Metallurgical Engineering; Electrotechnical, Petroleum, Coal and Related Products; Electronics and Information Technology; Production and General Engineering; Food and Agriculture; Textile; Transport Engineering; Mechanical Engineering; Water Resources; Management & Systems; Service Sector Departments- I & II.

SSD- I & II formulate Standards on service sector including Banking and Financial Services; Education Services; Tourism Services; Accounting Services; Legal Services; Media & Entertainment Services; Health & Wellness Services; IT & ITES Services; Environment Services; Telecommunication Services; Infra & Construction Services; Transport & Logistics Services.

### **Certification and ISI Mark**

The BIS Act 2016, Rules and Regulations framed there under authorizes the Bureau to undertake conformity assessment of products, services, systems and processes.

The Product Certification Schemes of the Bureau aims at providing Third Party assurance of quality, safety and reliability of products to the customer. Presence of BIS certification mark, known as Standard Mark, on a product is an assurance of conformity to the specifications. The manufacturer is permitted to self-certify the licenced products after ascertaining its conformity to the Standard. Through its surveillance operations, the Bureau maintains a close vigil on the quality of certified goods. The conformity is ensured by regular surveillance of the licensee's performance by surprise inspections and testing of samples, drawn both from the market or factory.

The certification scheme operates through a network of 41 Branch Offices set up in State capitals or major industrial towns and 5 Regional Offices overseeing the work of the Branch offices. Although, the scheme itself is voluntary in nature, the Government of India, on considerations of public health and safety, security, infrastructure requirements and mass consumption has enforced compulsory certification on various products through Orders issued from time to time under various Acts.

### **Registration and Mark**

Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) has notified "Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012" on 03 October 2012 for fifteen categories of electronics items. Fifteen more product categories were added by MeitY under this order on 13 November 2014. MeitY has also notified Indian Standard for 'Indian Language Support for Mobile Phones' on 24 October 2016. Another thirteen product categories were added by MeitY under this order on 23 August 2017.

Ministry of New and Renewable Energy(MNRE) has notified five products under Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017 dated 05 September 2017.

As per the Orders, no person shall manufacture or store for sale, import, sell or distribute goods which do not conform to the Indian standard specified in the order and do not bear the Standard Mark with unique registration number obtained from the Bureau.

Bureau of Indian Standards grants licence to the manufacturers to use or apply Standard Mark with unique R-number, through registration based on self-declaration of conformity for goods and articles as per Indian Standards. The grant of licence and its operation under Compulsory

Registration Scheme are carried out as per the conformity assessment scheme under Scheme - II of Schedule - II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018'.

### **Laboratory Services**

To protect consumer's interest, the Bureau operates various conformity assessment schemes. Under these schemes, the Bureau grants licenses or registrations to such manufacturers who are capable of producing goods conforming to relevant Indian Standards, on continuous basis. To support these schemes, which requires testing of products on regular basis for checking conformity to the relevant Indian Standards, the Bureau has established a network of eight laboratories.

### **Hallmarking and Hallmark**

Hallmarking is the accurate determination and official recording of the proportionate content of precious metal in precious metal articles. The principle objectives of the Hallmarking Scheme are to protect the public against adulteration and to obligate manufacturers to maintain legal standards of fineness. In India, at present two precious metals namely gold and silver have been brought under the purview of Hallmarking.

The BIS Hallmarking Scheme has been aligned with International criteria on hallmarking. As per this scheme, Registration is granted to the jewellers by the Bureau under Hallmarking Scheme. The BIS certified jewellers can get their jewellery hallmarked from any of the BIS recognized Assaying and Hallmarking Centres. The recognition of an Assaying and Hallmarking Centre is done against IS 15820.

The list of list of registered jewellers and BIS recognised A&H centres is available on the Bureau's website, [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in).

Hallmarked Jewellery consist of following four marks:

1. BIS Mark
2. Purity in carat and fineness for gold (e.g.22K916,18K750, 14K585)  
In case of silver only fineness of 990,970,925,900,835,800
3. Assay centre's identification mark or number
4. Jewellers identification mark/number

### **Management System Certification and Marks**

Bureau of Indian Standards has been operating Management Systems Certification Scheme since 1991.

Initially, the Bureau started the scheme with Quality Management System Certification (IS/ISO 9001) and over the years it has gradually expanded its activities to various other Management Systems.

### **National Building Code (NBC)**

The National Building Code of India (NBC), a comprehensive building Code, is a national instrument providing guidelines for regulating the building construction activities across the country. It serves as a Model Code for adoption by all agencies involved in building construction

works be they Public Works Departments, other government construction departments, local bodies or private construction agencies. The Code mainly contains administrative regulations, development control rules and general building requirements; fire safety requirements; stipulations regarding materials, structural design and construction (including safety); building and plumbing services; approach to sustainability; and asset and facility management.

**Indian Standard on National Flag (IS 1):**

The design of the National Flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22 July 1947, and as decided by the Govt. of India, the First National Standard on National Flag was published as IS 1 in 1951 by National Flag Sectional Committee of ISI. This standard was then revised in 1964 with a view to completely change its dimensions in metric system subsequent to its adoption by the Government

For more details, please visit [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)



## **ANNEXURE V**

### **Gist of the provisions of Rule 144 (xi) of General Financial Rules 2017**

Orders issued by the Government of India restricting procurement from bidders of certain countries which shares a land border with India shall apply to this procurement.

- 1) Any bidder from a country which shares a land border with India (may be seen from the link <https://mea.gov.in/india-and-neighbours.htm>), excluding countries as listed in the website of Ministry of External Affairs, to which the Government of India has extended lines of credit or in which the Government of India is engaged in development projects (may be seen from the link <http://meadashboard.gov.in/indicators/92>) – hereinafter called 'Restricted Countries') shall be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Registration Committee constituted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). The bidders shall enclose certificate in this regard in the prescribed format.
- 2) "Bidder" (including the term 'Bidder', 'consultant' or 'service provider' in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.
- 3) "Bidder from such Restricted Countries" for the purpose of this clause means: -
  - (a) An entity incorporated, established, or registered in such a country; or
  - (b) A subsidiary of an entity incorporated, established, or registered in such a country; or
  - (c) An entity substantially controlled through entities incorporated, established, or registered in such a country; or
  - (d) An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or
  - (e) An Indian (or other) agent of such an entity; or
  - (f) A natural person who is a citizen of such a country; or
  - (g) A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above
- 4) The beneficial owner for the purpose of (3) above shall be as under:
- 5) (a) In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.
  - (b) Explanation-
    - (i) "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of shares or capital or profits of the company.
    - (ii) In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership.
    - (iii) In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;
    - (iv) Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.
    - (v) In case of a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
    - (vi) An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person

## **ANNEXURE VI**

### **Declaration regarding Blacklisting, Litigations or Criminal Offence or Conviction** **On letterhead of the bidder**

I/We hereby declare that our firm or Company is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/ State Government or PSU or other bodies under the Central Government/ State Government.

I/We also declare that no criminal case is registered or pending against the firm or company or its owner or partners or directors anywhere in India. I/We further declare that neither I/we nor our firm/ Company is found guilty of any criminal offence or convicted by any Court of Law

Dated the .....day of .....2021.

Signature of Bidder \_\_\_\_\_

Name & Address of Bidder \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Seal of the Firm/ Company

## **ANNEXURE VII**

### **Declaration regarding Termination of Previous Contract and Conflict of Interest** **On letterhead of the bidder**

I or We hereby declare that our firm or agency including their affiliates or subsidiaries or constituents:

- (a) has not had its previous contract terminated by the Procuring Organisation in the previous two years (from the date of opening of the bids for this EoI) for Contractor's default
- (b) does not have a conflict of interest as laid down in the EoI which substantially affects fair competition.

Dated on the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2021

**Signature of Bidder** \_\_\_\_\_

Name & Address of Bidder \_\_\_\_\_

Seal of the Bidder

**ANNEXURE VIII**

**DECLARATION FOR ABIDING BY THE CODE OF INTEGRITY IN PUBLIC  
PROCUREMENT (CIPP)**

**On letterhead of the bidder**

I or We hereby declare that I or We will abide by the Code of Integrity for Public Procurement (CIPP) as envisaged and prescribed in General Financial Rules, 2017.

I or We hereby further declare that in case of any transgression of this code, my or our name shall not only be liable to be removed from consideration for the present EoI and from the list of registered contractors or contractors or consultants or service providers (if already registered), but I or We will be liable for other punitive actions such as cancellation of contracts, banning and blacklisting or action in Competition Commission of India as provided in the GFR, 2017 and other governing procurement guidelines.

Date the ..... day of ..... 2020

**Signature of Bidder**\_\_\_\_\_

Name & Address of Bidder\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Seal of the Firm or Company

## **ANNEXURE IX**

### **INTEGRITY PACT**

"The Bureau" And "The Contractor" hereby agree not to indulge in any corrupt practices including without limitation any activity or action to influence the transaction on any aspect of contract and commit to take all measures necessary to prevent corruption maintaining complete transparency and fairness in all activities related to the Bureau. Users agree to follow and adhere with the Integrity Pact guidelines as under:

#### **Preamble**

The Bureau values full compliance with all relevant laws of the land, regulations, economic use of resources and of fairness or transparency in its relations with its Contractor (s).

#### **Section 1- Commitments of the Bureau.**

1. The Bureau commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:

- a. No employee of the Bureau, personally or through family members, will in connection with the bid for, or the execution of a person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
- b. The Bureau will during the bid process treat all bidders with equity and reason. The Bureau will in particular, before and during the bid process, provide to all Contractor(s) the same information and will not provide to any Contractor(s) confidential or additional information through which the Contractor(s) could obtain an advantage in relation to the process or the contract execution.
- c. The Bureau will exclude from the process all known prejudiced persons.

2. If the Bureau obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC or PC Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Bureau will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

#### **Section 2- Commitments of the Contractor(s)**

1. The Contractor(s) commits himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the bid process and during the contract execution.

- a. The Contractor(s) will not, directly or through any other persons or firm, offer promise or give to any of the Bureau's employees involved in the bid process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he or she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage before or during the execution of the contract.
- b. The Contractor(s) will not enter with other bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
- c. The Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC or PC Act; further the Contractor(s) will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Bureau as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
- d. The Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.

2. The Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

### **Section 3: Disqualification from bid process and exclusion from future contracts**

If the Contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2 of this pact or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Bureau is entitled to disqualify the Contractor(s) from the bid process or take action as per the procedure mentioned in the "Incident Management Policy" available on GeM portal or any other governing guidelines.

### **Section 4: Compensation for Damages**

1. If the Bureau has disqualified the Contractor(s) from the bid process prior to the award according to Section 3 of this pact, the Bureau is entitled to invoke the Bid Security Declaration so as to adequately compensate the Bureau on account of the same.
2. If the Bureau has terminated the contract according to Section 3 of this pact, or if the Bureau is entitled to terminate the contract according to Section 3 of this pact, the Bureau shall be entitled to demand and recover from the Contractor damages of the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

### **Section 5: Previous Transgression**

- I. The Contractor declares that no previous transgressions occurred in the last five years with any Government Organization, Autonomous organisation, PSU etc. that could justify his exclusion from the bid process.
- II. If the Contractor makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the bid process and action can be taken as per the procedure mentioned in "Incident Management Policy" of the GeM portal or any other governing guidelines.

For and on behalf of the Bureau  (Name of the Officer and Designation)(Office Seal)	For and on behalf of 'Bidder/ Contractor'  (Name of the Officer and Designation)(Office Seal)
---	---